

2
के राजनीतिक इतिहास में "शिमला सम्मेलन" एक दुर्घटना है। यह प्रथम
अवसर था कि जबकि भारत और ब्रिटेन के बीच आधारभूत राजनीतिक प्रश्न
पर नए, वरुण विभिन्न भारतीय वर्गों को विभाजित करने वाले साम्प्रदायिक प्रश्न
पर असफल हो गईं। "आजाद के ही शब्दों में, "यदि जिन्ना के निरीषदों के
किसी सम्मेलन में न ही गया होता तो परिणाम यह होता कि 14 सदस्यों
की परिषद में 7 मुसलमान होते, जबकि उनकी संख्या भारत में लगभग
एक चौथाई ही थी। यह कांग्रेस की उदारता का प्रमाण था और मुस्लिम
लीग की मुखर्ता का।" इस प्रकार 'शिमला सम्मेलन' जिन्ना की हठधर्मी
के कारण असफल हुआ। कुछ लोग इसे ब्रिटिश-पाल भी कहते हैं।
मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार के बीच गहरी सांठ-गांठ थी जिसका
जिन्ना ने फायदा उठाया।

(समाप्त)

डॉ० राजू मीची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी.के. कॉलेज, दुमरांव
दिनांक 27/08/2020

क्रिप्स प्रस्ताव (CRIPPS MISSION PLAN)

1

सन 1941 का वर्ष समाप्त हो रहा था कि एक महत्वपूर्ण घटना ने विश्वभूट को एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा कर दिया जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज अमेरिका की भूट में सन्तुलित हो गया। यह घटना 6 दिसम्बर को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान की भूट सफलताओं ने भारत के महत्व को विशेष रूप से बढ़ा दिया। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी और वह तब तक संभव नहीं था जब तक ब्रिटिश सरकार भारत में इस संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए किसी नयी नीति की घोषणा न करे। रंगून पर जापान के अधिकार के छह चार दिन बाद 11 मार्च 1942 को नर्विल ने स्टेट्स क्रिप्स को इस समस्या के समाधान के संदर्भ में भारत भेजने के निर्णय की घोषणा की। क्रिप्स एक सफल राजनयिक माने जाते थे। वे समानवादी विचारधारा के नेता थे तथा रूस के साथ संबंध बनाने में उन्होंने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। वे भारतीय नेताओं से भी परिचित थे और उन्हें जवाहरलाल नेहरू का मित्र माना जाता था। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत आए। उन्होंने भारत के विभिन्न दलों से बातचीत की तथा उसके बाद भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसे 'क्रिप्स प्रस्ताव' कहा जाता है।

क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के कारण — क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के निम्न लिखित कारण थे —

- (i) **जापान का स्वतंत्रता** — क्रिप्स को भारत भेजने का पहला और तात्कालिक कारण भूट की विगड़ती हुई स्थिति और भारतीय संकट था। जापानी सेनाएँ फिलीपाइन, मलाया, इण्डोनेशिया, इंडो-चाइन, सिंगापुर पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। इसके बाद वे भी को रॉडनी हुई भारत की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी थी।
- (ii) **ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव** — भारत की राजनीतिक गुल्मी को सुलझाने के लिए ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्र भी बराबर दबाव डाल रहे थे। पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद यह दबाव और तेज हो गया था। अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन को बताया कि स्टार्टाइट-चार्टर भारत पर भी लागू होता है, उसे भी आत्मनिर्णय का अधिकार है। दुखदी और चीन के राष्ट्रपति मार्शल चॉंग काई शेंक ने भारतीयों से भूट में मंत्रीओं की सहायता देने की अपील की तथा राष्ट्रपति ने ब्रिटिश सरकार से भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए दबाव डाला। आस्ट्रेलिया के विदेशमंत्री डॉ० इवाट ने भी भारत की स्वतंत्रता की मांग का जोरदार आह्वान किया।
- (iii) **ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटेन के दूसरे प्रभावशाली सदस्यों ने**

काँग्रेस द्वारा क्रिष्ण प्रस्तावों को अस्वीकृति - काँग्रेस ने निम्न कारणों से क्रिष्ण प्रस्तावों को ठुकरा दिया।

- (i) ऑपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की कोई अवधि निश्चित नहीं की गयी थी।
- (ii) संविधान सभा में देशी रिजासतों के प्रतिनिधियों को उनके नरेश नामजद करें, वह-चाहती थी कि उनका जनता द्वारा निर्वाचन होना-चाहिए।
- (iii) क्रिष्ण योजना में परीय रूप से न केवल पाकिस्तान निर्माण की माँग को स्वीकार कर लिया गया था वलिक प्रान्तों को यह स्वतंत्रता भी दी जा रही थी कि वे-चाहे तो नई जनसभा बनाने लें।
- (iv) अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सरकार एक संघि भी करना-चाहती थी और संघि की माँ स्पष्ट नहीं थी।

(v) क्रिष्ण प्रस्तावों में काँग्रेस की दो माँगों को ठुकरा दिया गया था। प्रथम यह कि वायसरॉय नाममात्र के प्रधान के रूप में काम करें और दूसरा यह कि बुरज एक राष्ट्रीय दरबार का निर्माण होना-चाहिए।

क्रिष्ण प्रस्तावों की लीग द्वारा अस्वीकृति :- ॥ अप्रैल 1942 की मुस्लिम लीग ने प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान निर्माण की माँग को स्वीकार नहीं किया गया। लीग मुख्तगानों के लिए प्रथम संविधानसभा-चाहती थी। क्रिष्ण प्रस्तावों से शिरकों, हरिजनों तथा हिन्दू महासभा ने ठुकरा दिया। सिखों का मत था कि पंजाब को भारत से अलग नहीं होने देंगे। उदारवादी नेता सरनेज बहादुर सप्रु, डॉ जयकर आदि ने 'क्रिष्ण योजना' को आत्मनिर्माण के सिद्धान्त का उपहास कहकर ठुकरा दिया। हिन्दू महासभा ने क्रिष्ण प्रस्ताव को 'पीढ़े के दरबाने से पाकिस्तान की स्थापना की चेष्टा' तथा भारत के बलकानिस्तान (देशको अनेक टुकड़ों में बाँटने की-चाह) कहकर अस्वीकार कर दिया।

जब भारत के प्रमुख पलों ने क्रिष्ण के सुझावों को मानने से इंकार कर दिया तो क्रिष्ण ने ॥ अप्रैल 1942 को इन सुझावों को वापस ले लिया।

निष्कर्ष :- क्रिष्ण मिशन से कोई भी खुश नहीं हुआ। प्रस्तावों को अचानक ॥ अप्रैल 1942 को वापस ले लिया गया। इतना मिशन ही विफलता का मुख्य कारण यह था कि क्रिष्ण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दसके लिए संतोषप्रद सिद्ध नहीं हुए। शायद ही, ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थी। डॉ० पट्टाभिशिरीरमैय के अनुसार क्रिष्ण प्रस्तावों में विभिन्न खमियों को संतुष्ट करने के विभिन्न पर्याय थे, और काँग्रेस के लिए ऑपनिवेशिक स्वराज्य और संविधान सभा, मुख्तम लीग के लिए डिली प्रान्त को भारत से अलग होने का अधिकार और देशी नरेशों के लिए संघ में शासिक भूमि था न होने का स्वेच्छाधिकार। फलतः यह प्रस्ताव किसी को संतुष्ट नहीं कर सका।

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी०के० कॉलेज, दुमरांव
दिनांक 26/08/2020

REDMINGTON 6 PRO
MI DUAL CAMERA